

**एक नजर**

**कोडीन कफ सिरप तस्करि मामले में 8.95 लाख रुपये कर्फ**



—भारतीय बस्ती संवाददाता—  
बस्ती। नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय को कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करि मामले में बड़ा कदम उठाया है। अवलगत में मुख्य आरोपी के बैंक खाते में जमा 8 लाख 95 हजार 548 रुपये की 6 नगरीय को अग्रहण से अर्जित संपत्ति माहौल हुए कुर्क करने का आदेश दिया है।

अपर सन न्यायाधीश विजय कुमार कटवार ने मामले की सुनवाई करते हुए गणपति फार्मा से जुड़े आरोपी पंचम कुमार के वाराणसी स्थित एक निजी बैंक खाते में जमा राशि को तत्काल प्रभाव से फ्रीज करने के निर्देश दिए। न्यायालय के आदेश के बाद संबंधित बैंक को उक्त नगरीय को सुरक्षित रखते हुए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

अभियोग पत्र के अनुसार, आरोपी पंचम कुमार का बैंक कोडीन युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप के अवैध कारोबार से रहा है। जहां एजेंसियों की रिपोर्ट में सामने आया कि आरोपी फर्म के नाम से संचालित बैंक खाता का उपयोग अवैध वित्तीय लेनदेन के लिए किया जा रहा था और खाते में जमा 6 नगरीय इतनी अवैध धन से अर्जित की गई थी।

बैकवाहिकारी सदर सचिव मृगुण तिहारी ने बताया कि बिना कोतवाली बस्ती में वर्ष 2023 में मुद्रणदा अपरफार्म। संख्या 46682029 एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं में चर्च किया गया था। जांच के दौरान कई अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और उन्हें जिला कारागार भेजा गया। इसी मामले में बोगस फर्म गणपति फार्मा के मालिक पंचम कुमार को भी गिरफ्तार कर न्यायिक अग्रहण में निरूद्ध किया गया है।

तिहारी ने यह भी बताया कि जांच में सामने आया अवैध कारोबार के आधार पर न्यायालय के आदेश से आरोपी को वाराणसी स्थित बैंक खाते में जमा 8.95 लाख रुपये की राशि कुर्क करवाई गई है। साथ ही, मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की संश्लेषण की भी तस्करि की जा रही है और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के जल्दीकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

**युवक ने फांसी लगाकर जान दिया**



—भारतीय बस्ती संवाददाता—  
बस्ती। रूबीली थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। यह घटना 14 मार्च 2026 को रूबीली के वार्ड नंबर 14, शारदी नगर में हुई। मृतक की पहचान अरुण मिश्र उर्फ खिनूक (लगभग 32 वर्ष) पुत्र राम युद्ध मिश्र की रूप में हुई है। प्रभारी निरिक्षक संजय दुबे ने बताया कि मृतक अरण्य के संजय दुबे से गले में फांदा लगाकर आत्महत्या की है। परिजनो ने उसे फंदे से उतार दिया था। उसका शव एक गोदाम के अंदर फंसे पर पड़ा मिला। पुलिस को घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनो से तहरीर प्राप्त की है और पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया कर रही है।

**युद्ध के बीच भारतीय जहाज रवाना, दूर होगा गैस का संकट**



नई दिल्ली (आभा)। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एलपीजी को लेकर शनिवार को दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग में अहम बयान दिया। उन्होंने बताया कि कुछ जहाज जो भारत के लिए रवाना हुए थे, वे स्ट्रैंट ऑफ मोजम्बिक से सफलतापूर्वक गुजर चुके हैं। 2 भारतीय जहाजों (शिवालिक और नंदा देवी) ने इस जलअभ्रमण्य को पार किया है और अब वे भारत के बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इन दोनों जहाजों में से प्रत्येक में 46,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी लदा हुआ है, जिससे कुल मिलाकर 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित हो

रही है। उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में कई भारतीय जहाज अभी भी स्ट्रैंडजाय पर हैं। भारत सभी संबंधित देशों के साथ संपर्क में बना हुआ है ताकि जहाजों का सुरक्षित और निरंतर आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। यह प्रयास भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि क्षेत्र में बस्तुओं और ऊर्जा के निर्यात परिवहन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत ने नागरिक बुनियादी ढांचे, विशेषकर ऊर्जा ढांचे को मिशाना बनाने से बचने की अपील की है। उनका मानना है कि यह वैश्विक समुदाय का भी एक प्रमुख प्राथमिकता है। संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए भारत ने सभी महत्वपूर्ण पक्षों से संपर्क बनाए रखा है।

**कड़ी सुरक्षा में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा**

—भारतीय बस्ती संवाददाता—  
बस्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित उप निरिक्षक नागरिक कॉलेज एवं सफाई पट्टों की सीधी नवी लिखित परीक्षा के महानगर जिलाधिकारी कृतिष्ठा को जल्दतना ने शनिवार को जिले में बनाए गए परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने महिला डिग्री कॉलेज, पीएन डिग्री कॉलेज और गोविंद राम सेकेंडरी इंटर कॉलेज

**एरियर भुगतान के नाम पर रिश्वत लेने वाला निलम्बित**

—भारतीय बस्ती संवाददाता—  
बस्ती। समुदायिक स्वस्थ केंद्र (सीएसके) विक्रमजीत में एक बरिष्ठ सहायक पर महिला स्वस्थकर्मी से रिश्वत लेने का आरोप लगा है। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद स्वस्थ विभाग में हड़कंप मच गया है। मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएसके) डॉ. राजीव निगम ने आरोपी कर्मचारी के निलंबन की सिफारिश करते हुए शासन को पत्र भेजा है। पीठिया सुनीता वर्मा ने बताया कि उनका एरियर काफ़ी समय से बकाया था, जिसके भुगतान के लिए कोई नई आदेश जारी किया था। आरोप है कि विक्रमजीत सीएसके में तैनात बरिष्ठ सहायक प्रदीप श्रीवास्तव ने इस भुगतान को जारी करने के बदेन कुल राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा मांगा। सुनिता वर्मा के अनुसार, उन्होंने भुगतान करवाने के दबाव में आकर अब तक दो किरतों में कुल 45,000 रुपये दिए हैं। पहली किरत में 25,000 रुपये और दूसरी किरत में 20,000 रुपये का भुगतान किया गया। पीठिया का आरोप है कि आरोपी प्रदीप श्रीवास्तव अब भी दबाव बना रहा है कि जब तक वे 10 प्रतिशत का पूरा हिस्सा (जो कि 1 लाख रुपये से अधिक है) नहीं मिला जाता, तब तक एरियर जारी नहीं किया जाएगा। पीठिया सुनीता वर्मा ने कहा, मुझे हर काम के लिए पैसा मांगा जा रहा है। कोर्ट का आदेश होने के बावजूद बिना कमीशन के पैसा जायज हक मुझे नहीं दिया जा रहा।

**विद्यालय प्रबंध समिति शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी - विजय आनन्द**



—भारतीय बस्ती संवाददाता—  
बस्ती। उर्ध्वाधीनता के प्रमाण में शनिवार को विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्षों और प्रधानाध्यापकों की एक दिवसीय कार्यशाळा खण्ड शिक्षा अधिकारी विजय आनंद की अध्यक्षता में संचालन हुई। कार्यशाळा में दर्जक के समी 159 परिषदीय विद्यालयों के एएसएमसी अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापक ने भाग लिया। प्रिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाना, वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रदर्शिता सुनिश्चित करना तथा विद्यालय विकास में सतुद्युग की सक्रिय भागीदारी को सशक्त बनाना था। कार्यशाळा को संबोधित करते हुए खण्ड शिक्षा अधिकारी ने कहा

**कार्यशाळा में विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने पर चर्चा**

कि विद्यालय प्रबंध समिति शिक्षा व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने जोर दिया कि यदि समिति अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी, विश्वास, मनीष पाण्डेय और लवकुश त्रिपाठी ने विस्तृत रूप से एएसएमसी अध्यक्षों और प्रधानाध्यापकों कार्य दायित्व एवं विद्यालय संचालन के बारे में बताया। प्रिक्षकों ने बात अधिकार एवं बाल अधिकारों का संरक्षण, निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार, विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना, गठन, कार्यकाल, विद्यालय प्रबंध समिति के दायित्व, वित्तीय विकास, विद्यालय विकास योजना, स्थानीय प्राधिकारों के कार्य एवं दायित्व, वैदक रजिस्ट्रार, शाखा कार्यक्रम के अंतर्गत आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हाकन, विद्यार्थी एवं युवायुक्तों की जांचकारी, समग्र शिक्षा का संचालन ऑनलाइन, बालिका शिक्षा एवं प्री स्कूल, निगुण भारत मिशन एवं गुणवत्ता शिक्षा, ऑनपरिणत कायाकल्प में एएसएमसी के कार्य एवं दायित्व, मूल्यांकन योजना, अभिभावक एवं सामुदायिक भागीदारी आदि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया। इस अवसर पर शिक्षक संघ के अध्यक्ष विरामचंद्र वर्मा, रामपिण्डरी, अरुण कुमार, प्रेम सागर सहित बड़ी संख्या में प्रधानाध्यापक और एएसएमसी अध्यक्ष उपस्थित रहे।

**सफाई कर्मचारी संघ के चुनाव का मामला फिर गरमाया: निष्पक्ष जांच, कार्यवाही की मांग**



—भारतीय बस्ती संवाददाता—  
बस्ती। उत्तर प्रदेश पंचायती राज प्राणिक संघ कर्मचारी संघ के चुनाव को लेकर विवाद एक बार फिर गरमा गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री जनसुश्रुता गठन पर शिकायत दर्ज करते हुए चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाया गया है। इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच और तथ्यो से निदेशक पंचायतीराज को अलग करवाये जाने की मांग किया गया है। शिकायत के अनुसार संघ के प्रांतीय कार्यालय द्वारा 17 दिसम्बर 2025 को जारी पत्र के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया में द्विपक्षीय अधिेशन चुनना कराने हेतु सिद्धांतगत रूप से जिला अध्यक्ष रणजीत कुमार को चुनाव अधिकाधिकार प्रकिया गया था। आरोप है कि 25 दिसम्बर 2025 को होने वाले नामांकन की सूचना को तो सार्वजनिक रूप से जारी की गई और न ही स्थान की जानकारी दी गई। साथ ही जिला मंत्री मनोज चौहान, कोषाध्यक्ष पेशकार और

**सफाई कर्मचारी संघ के चुनाव का मामला फिर गरमाया: निष्पक्ष जांच, कार्यवाही की मांग**

में साक्षा की गई। साथ ही चुनाव के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी से अनुमति लेने और जिले के सफाई कर्मचारियों की सत्यापित सूची मंगाने की प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई। बताया गया कि इस घटनाक्रम से कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया, जिसके बाद सफाई कर्मचारी संघ ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विचार अधिकारी, डीपीआरओ एवं ससस्त कड़ीओं पंचायत को सूचना देते हुए अटल बिहारी प्रशादगं में

**रिहा होंगे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक**



नई दिल्ली (आभा)। केंद्र सरकार ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और ईजीनियर सोनम वांगचुक की नजरबंदी को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास को माहौल बनाने तथा सभी हिताधारकों के साथ सार्थक संवाद को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। सरकारी बयान के अनुसार, लेह

कि वह इस अधिनियम के तहत निर्धारित हितसहित अवधि का लगभग आधा समय बच चुके हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि सरकार लद्दाख के विभिन्न समुदायों और हितधारकों के साथ लगातार संवाद कर रही है ताकि क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं और विताओं का समाप्त आंकड़ा जा सके। हालांकि, लगातार बंद और प्रदर्शनों के कारण क्षेत्र की सामाज्य स्थिति और अव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

**घरेलू गैस सिलेण्डर संकट के विरोध में आप ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को भेजा 4 सूत्रीय ज्ञापन**



—भारतीय बस्ती संवाददाता—  
बस्ती। शनिवार को बस्ती महंगाई और घरेलू गैस सिलेण्डर की कीमतों में वृद्धि के विरोध में आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने कंधों पर सिलेण्डर लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद आप जिलाध्यक्ष डा. राम सुभाष वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप जायसवाल और प्रदेश सचिव पतिराम पतिराम आजद के नेतृत्व में जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को 4 सूत्रीय ज्ञापन भेजकर समस्याओं के निराकरण कराने की मांग किया। 4 सूत्रीय ज्ञापन में कहा गया है कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर के दामों में वृद्धि को तत्काल प्रभाव से वापस लेने के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ङोस और पारदर्शी नीति लागू की जाए। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को रसोई गैस पर विशेष सब्सिडी दिये जाने के साथ ही महंगाई पर कंट्रोल कारोबारियों के सामने गंभीर संकट और जवाबदेह नीति घोषित करें।

ज्ञापन देने के बाद आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष डा. राम सुभाष वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप जायसवाल और प्रदेश सचिव पतिराम पतिराम आजद के नेतृत्व में जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को 4 सूत्रीय ज्ञापन भेजकर समस्याओं के निराकरण कराने की मांग किया। 4 सूत्रीय ज्ञापन में कहा गया है कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर के दामों में वृद्धि को तत्काल प्रभाव से वापस लेने के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ङोस और पारदर्शी नीति लागू की जाए। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को रसोई गैस पर विशेष सब्सिडी दिये जाने के साथ ही महंगाई पर कंट्रोल कारोबारियों के सामने गंभीर संकट और जवाबदेह नीति घोषित करें।

**टेट के सवाल को लेकर शिक्षकों द्वारा पाती भेजने का अभियान जारी**



—भारतीय बस्ती संवाददाता—  
बस्ती। टेट की अनिवार्यता समाप्त किये जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक संघ के आवाहन पर शिक्षकों ने राष्ट्रीय, प्रान्तीय, मुख्य व्यापकोश, मुख्यमंत्री (उ.प्र.), नेता प्रतिपक्ष भारत और युपी को शिक्षकों की पाती भेजने का सिलसिला शनिवार को भी जारी रखा। शिक्षकों से पाती भेजकर मांग किया कि टेट की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कराया जाए। यह जानकारी देते हुये उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष एवं अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक संघ के संयोजक उदयशंकर शुक्ल ने बताया कि शनिवार को परशुमामपुर ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों पर जाकर कार्यवाहक अध्यक्ष नरेन्द्र द्विवेदी के नेतृत्व में टीईटी के विद्ये में संगठन के साथ ही आगामी 13 अप्रैल को जनपद स्तर पर महाां जुलूस और 3 मई को उत्तरांचल में आजातिय महारैली में हिस्सा लेने के लिये प्रेरित कर रहे हैं। शिक्षकों की पाती पर हस्ताक्षर करारक संचयित को डाक और ई मेल से भेजा जा रहा है। इसके साथ ही जनपद के अनेक अनेक हिस्सों में शिक्षकों द्वारा

दवाव कर रहा है कि घरेलू गैस का कोई संकट नहीं है जबकि लोग परेशान हैं और गैस के लिये लम्बी कतारें हैं। मांग किया कि केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से समस्या का समाधान निकाले। ज्ञापन और प्रदर्शन कराने वालों में बंधुमान कर्नोजिया, धीरेन्द्र कुमार यादव, राम सागर सूर्यवंशी, अमित जायसवाल, उमेश कुमार शर्मा, मिथिलेश भारती, अब्दुल क़दुम के साथ ही पार्टी के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल रहे।

**—सफलाता मिलने तक जारी रहेगा आन्दोलन— उदयशंकर शुक्ल**

के पदाधिकारियों द्वारा मांग पत्र पर शांति में हिस्सा लेना जारी रहेगा। हस्ताक्षर के दौरान संगठन के ससस्त पदाधिकारियों को अवरोध उच्च प्राथमिक विद्यालय जटौलिया के शिक्षकों द्वारा सम्मानित किया गया। शिक्षकों से पाती भेजकर मांग किया कि टेट की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कराया जाए। यह जानकारी देते हुये उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष एवं अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक संघ के संयोजक उदयशंकर शुक्ल ने बताया कि शनिवार को परशुमामपुर ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों पर जाकर कार्यवाहक अध्यक्ष नरेन्द्र द्विवेदी के नेतृत्व में टीईटी के विद्ये में संगठन के साथ ही आगामी 13 अप्रैल को जनपद स्तर पर महाां जुलूस और 3 मई को उत्तरांचल में आजातिय महारैली में हिस्सा लेने के लिये प्रेरित कर रहे हैं। शिक्षकों की पाती पर हस्ताक्षर करारक संचयित को डाक और ई मेल से भेजा जा रहा है। इसके साथ ही जनपद के अनेक अनेक हिस्सों में शिक्षकों द्वारा

इस अवसर पर संरक्षक, सत्रीश शंकर शुक्ला दिनेश वर्मा कोषाध्यक्ष पंच बहादुर यादव,पाणिनी नगरी, विवेक तिवारी, भारत राम नगरी, अखिल भारतीय, साधना शिवारी, नीतू पाण्डेय, शुक्ल मंजु, अंम प्रकाश, अरविंद जायसवाल, राजेश कुमार यादव, जाकिर हुसैन, गुरु लाल वर्मा, हरिप्रसाद शिक्षक उपस्थित रहे।

**ग्लूकोमा से बचाव की दिये जा जानकारी**



—भारतीय बस्ती संवाददाता—  
बस्ती। शिववंश क्लिनिक पीजी कॉलेज के सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में अंतरराष्ट्रीय न्यूकोमा दिवस के उपलक्ष्य में न्यूकोमा (आँखों की गंभीर बीमारी) के प्रति रणपरस्पर की दोनों इकाइयों ने जूनापुत्र चंद्र बोस एवं जर्म लक्ष्मी बाबू तथा मा गायत्री फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों, स्वयं सेवकों, न्यूकोमाओं तथा प्राध्यापकों को न्यूकोमा के कारण, लक्षण और बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आचार एवं पोषण विशेषज्ञ नीरज पाण्डेय ने बताया कि न्यूकोमा आँखों

संस्था के प्रबंधक नीरज पाण्डेय राष्ट्रीय सेवा योजना के दोनों इकाइयों के संसर्क और निवेश, महाविद्यालय, डॉ. प्रभात शर्मा, डॉ. प्रियेश चौरविया, डॉ. अक्षय कुमार, डॉ. हरि अम पटेल, अभिनव मिश्रा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक व सेविदाय तथा स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का निष्ठाकर्ता है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिपा

# दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 15 मार्च 2026 रविवार

## सम्पादकीय बेखौफ अपराधी

उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दावे करती रही है कि राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। मगर पिछले कुछ समय से लगातार अपराध, लूटपाट और हत्या के बढ़ते मामलों ने दावों की कलाई खोल दी है। अपराधी बेशक बाद में पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन सच है कि वे वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे। सवाल है उनके भीतर पुलिस का खौफ क्यों नहीं दिखता। पिछले दिनों संभल में कुछ लोग एक युवक को घर से खींच कर ले गए और उसकी बेरामी से हत्या कर दी। इस घटना को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि बदमाशों ने गुरुवार को हिंदुस्तान पेट्रोलियम के इस्थानाल संयंत्र के दफ्तर में घुस कर दो वरिष्ठ अधिकारियों की गोली मार कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कारी सूची में डाले गए एक विक्रान्त ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पहले भी महाप्रबंधक को से अधिकारी की कार पर हमला कर चुका था। जब इस मामले की पुलिस और जिला प्रशासन स्तर पर शिकायत दर्ज करा दी गई थी, तो आरोपी पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

सवाल यह भी है कि फिर सुरक्षा वाले संयंत्र में हथियार लेकर वह कैसे घुसा? कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों पर अपराधी क्या जवाब दे रहे? उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है, तो स्पष्ट है कि राज्य के पूरे पुलिस घटनों में समन्वय का अभाव है। आए दिन हो रही हत्या की घटनाओं से समझा जा सकता है कि राज्य में अपराध पर लगातार लगने के दावे में दम नहीं है।

जमीनी सत्ताई नहीं है कि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। पुलिस की तन्मा कथित सख्ती और सक्रियता के बावजूद आपराधिक मानसिकता के लोगों में कानून और सजा का कोई डर नहीं है। ऐसा लगता है कि अपराध नियंत्रण में कहीं न कहीं कमजोर कड़ी रह गई है, जिसकी शिथिलता सख्ती की जा रही है।

आज स्थिति यह है कि लोग खुद को घरो से लेकर दफ्तरों तक सुरक्षित नहीं पा रहे हैं। आए दिन जघन्य अपराधों के महंजन पर उनकी विराएं नाहक नहीं हैं। सवाल है कि राज्य सरकार अपराध और अपराधियों पर काबू करने के जो दावे करती रही है, हकीकत उसके उलट क्यों दिख रही है।

## बढ़ती महंगाई, घटती आमदनी

जब किसी भी तरह के रोजगार से आय का स्तर उहरा हुआ हो, जरिया सीमित हो, तो आम आदमी की उम्मीद यही होती है कि बाजार में जरूरी वस्तुओं की कीमतें उसकी पहुंच में हों या फिर कम से कम स्थिर रहे। मगर पिछले कुछ वर्षों से आमदनी की तुलना को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को जितना खर्च करना पड़ रहा है, वह कई बार भी पड़ता है।

माना जाता है कि दिसंबर से फरवरी तक की अवधि में बाजार में सब्जियों की आकृष्टता होने की वजह से महंगाई काबू में रहेगी। मगर सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में खुदरा महंगाई फरवरी में बढ़ कर 3.21 फीसद हो गई। हालांकि जनवरी में यह 2.74 फीसद के स्तर पर रही थी। जाहिर है, सिर्फ एक महीने के भीतर जरूरी वस्तुओं की कीमतों में तेज इजाफा हुआ और यह पिछले दस महीने के सबसे उच्च स्तर पर बढ़ा दिया गया।

कहा जा सकता है कि फरवरी के आंकड़े के मुताबिक महंगाई दर धार फीसद से नीचे है, लेकिन यह भी देखने की जरूरत है कि कीमतों के संघर्ष में जरूरी सामान तक आम लोगों की पहुंच सिद्ध हद तक आसान है। यह ठिपा नहीं है कि रोजगार और आय की कसौटी पर देश की ज्यादातर आबादी के लिए स्थिति अब भी संतोषजनक नहीं है। लंबे समय से विद्युत आमदनी और कमजोर क्रयशक्ति की स्थिति में जब सबसे जरूरी चीजों पर लोगों का खर्च थोड़ा भी बढ़ता है, तो उसके लिए मुश्किल पैदा होती है।

फरवरी में महंगाई के आंकड़ों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण दरअसल खाते-पीने की चीजों के दामों में बढ़ोतरी रही। खुदरा महंगाई से इस बात को पता चलता है कि प्राकृतिक की खपत और खर्च की स्थिति बढ़ी है। इसी वजह से रिजर्व बैंक अपनी नीति धर करके समग्र खुदरा महंगाई को ही अपना आधार बनाता है। अगर खुदरा महंगाई की दर उसके तय दायरे यानी धार फीसद के बाहर बढ़ जाती है तो फिर कर्ज के सत्ता होने की उम्मीद भी कम हो जाती है।

महंगाई के सत्ता आंकड़े फरवरी के यह परिचय एशिया में युद्ध के हालात नहीं थे। अब पिछले कुछ दिनों से जिस तरह ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की सजा जंग चल रही है, उसका बाजार में थोक और खुदरा महंगाई पर क्या असर पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल, यह कड़ी वजह से रही संभव आभूतों को लेकर बढ़ती हुई कर्ज तृष्ट की आशाएं उमर रही थीं कि इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य के समुद्री मार्ग को बाधित कर दिया। इसके बाद उस रास्ते से भारत में भी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति व्यापक पैमाने पर बाधित हुई है और इसका असर बाजार पर कहीं तय माना जा रहा है। फिलहाल खाना प्रदान वाले गैस की कीमत में इजाफा और गैस सिलेंडरों की कमी की आशंका में लोगों के बीच मची अफरा-तफरी देखी जा सकती है। ऐसे में इस बात की आशंका गहरा रही है कि अगर युद्ध लंबा सिद्ध और कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित रही, तो भारत में भी पेट्रोल-डीजल के दाम पर भी इसका व्यापक असर पड़ सकता है। इसके बाद माल बुलाई में बढ़ोतरी के साथ स्वामित्व रूप से बाजार में मौजूद सवाल कोल्लेगी होगी। जाहिर है, सरकार को अपने बाद दिनों में हालात का आकलन कर महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की जरूरत है।

# इटावा का ऐतिहासिक चुनाव और बहुजन राजनीति का उभार



—अखिल कुमार यादव—

15 मार्च भारतीय राजनीति और सामाजिक न्याय के आंदोलन के इतिहास के एक महत्वपूर्ण तिथि है। इसी दिन बहुजन आंदोलन के महानायक काशीराम का जन्म हुआ था। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र में उन्नत वर्गों की आबाज को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया, जिन्हें सदियों तक सामाजिक और राजनीतिक सत्ता से दूर रखा गया था। काशीराम का पूरा जीवन इस विचार के लिए समर्पित रहा कि जब तक बहुजन समाजिक दल, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक राजनीतिक सत्ता में भागीदारी नहीं करेगा, तब तक सामाजिक सम्मान और बराबरी का सपना अचूक रहेगा। उनकी राजनीति केवल उनका जीवन के राजनीति नहीं थी, बल्कि सामाजिक चेतना को राजनीतिक शक्ति में बदलने की राजनीति थी। इसी कारण उन्हें भारतीय लोकतंत्र में बहुजन राजनीति के सबसे बड़े वास्तुकारों में गिना जाता है। काशीराम को राजनीतिक चेतना अचानक विकसित नहीं हुई थी। इसके पीछे लंबा वैचारिक अध्ययन और सामाजिक अनुभव था। उनकी सोच पर सबसे गहरा प्रभाव भीमराव रामजी आंबेडकर के विचारों का था, जिन्होंने दलितों और वंचित समाज के लिए सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ी। इसके साथ ही ज्योतिबा गोविंदराम फुले और ई.वी. रामास्वामी जैसे सामाजिक क्रांतिकारियों की विचारधारा ने भी काशीराम को प्रभावित किया। इन सभी विचारकों का साझा संदेश था कि सामाजिक असमानता को खत्म किए बिना लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ पूरा नहीं हो सकता।



काशीराम ने इन विचारों को केवल सिद्धांत के रूप में नहीं अपनाया, बल्कि उन्हें संगठित राजनीतिक आंदोलन का आधार बनाया।

सरकारी नौकरी के दौरान ही काशीराम को यह एहसास हुआ कि केवल सामाजिक आंदोलन से परिवर्तन संभव नहीं है, बहुजन समाज को राजनीतिक शक्ति हासिल करना भी जरूरी है। इसी सोच के साथ उन्होंने कर्मचारियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए बामफस का गठन किया। इसके बाद दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी डीएसएम का गठन हुआ, जिसने बहुजन समाज के बीच व्यापक राजनीतिक चेतना पैदा की। अंततः इस वैचारिक यज्ञ से बहुजन समाज पार्टी का स्थापना हुई, जिसने उत्तर भारत की राजनीति में एक नई धारा पैदा की। काशीराम केवल संगठनवादी ही नहीं बल्कि एक जनतावादी राजनीतिक विचारक भी थे। उनकी चर्चित पुस्तक चमत्ता मूल में उन्होंने एक प्रवृत्ति की आलोचना की जिसमें वंचित समाज के कुछ नेता समाज के प्रभाव में आकर अपनी ही समाज की वास्तविक समस्याओं से दूर हो जाते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक बहुजन समाज अपना स्वतंत्र नेतृत्व विकसित नहीं करेगा, तब तक सामाजिक न्याय की लड़ाई अरुि रहेगी। इसी विचारधारा को आगे

बढ़ाते हुए उन्होंने एक प्रभावशाली नारा दिया: "यह नारा धीरे-धीरे उत्तर भारत की राजनीति में सामाजिक प्रतिनिधित्व की मांग का प्रतीक बन गया। इसने बहुजन समाज के भीतर यह विश्वास पैदा किया कि लोकतंत्र में उनकी संख्या ही उनकी राजनीतिक शक्ति बन सकती है।

बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद भी संसद तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। शुक्राचाली चुनावों में पार्टी को सीमित सफलता मिली और कई जगह हार का सामना करना पड़ा। लेकिन काशीराम निरंतर नहीं रुके। वे लगातार संगठन मजबूत करने और जनता के बीच अपनी विचारधारा को प्रभाव में लाने रहे। वे गांव-गांव जाकर बैठकों और चौपालों के माध्यम से लोगों को यह समझाते थे कि राजनीतिक सत्ता ही सामाजिक सम्मान का रास्ता खोल सकती है। इसी संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट बहुजन राजनीति के लिए प्रतिभासिद्ध साबित हुई।

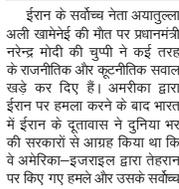
वर्ष 1991 का आम चुनाव बहुजन उत्तर प्रदेश की राजनीतिक मंडन और भी रोशनी का दौर था। इस बार कुल 48 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर आए। इसी बड़ी संख्या में प्रत्याशियों का मैदान में उतरना उनके लिए एक नई दिशा थी और सामाजिक न्याय का सवाल पूरे देश

में प्रमुख राजनीतिक युवा बन चुका था। इसी दौर में काशीराम ने इटावा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। इटावा उस समय समाजवादी राजनीति का मजबूत शिवनाम था। यहां यादव, शाय, कुर्मी और अन्य पिछड़े वर्गों के साथ-साथ दलित समाज की भी बड़ी आबादी थी। यह क्षेत्र लंबे समय से समाजवादी विचारधारा से प्रभावित रहा था और स्थानीय राजनीति के पिछड़े वर्गों की भूमिका मजबूत थी। लेकिन उनका बल ही औपचारिक बहुजन संघर्षों में उभारने का प्रतीक बन गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उस समय के मुख्य चुनाव आयोग टी.एन. शेषन को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने इटावा लोकसभा सीट का चुनाव निरस्त कर दिया। यह घटना उस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई और चुनाव आयोग की सख्ती की मिसाल के रूप में देखी गई।

जब दोबारा चुनाव की घोषणा हुई तो इटावा का राजनीतिक मैदान और भी रोशनी का दौर था। इस बार कुल 48 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर आए। इसी बड़ी संख्या में प्रत्याशियों का मैदान में उतरना उनके लिए एक नई दिशा थी और सामाजिक न्याय का सवाल पूरे देश

## खामनेई की मौत पर मोदी की चुप्पी के मायने

—योगेन्द्र योगी—



ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी ने कई तरह के राजनीतिक और कूटनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला करने के बाद भारत में ईरान के दूतावास ने दुनिया भर की सरकारों से आग्रह किया था कि वे अमेरिका-इजराइल द्वारा तेहरान पर किए गए हमले और उसके संभाव्य नेता अयातुल्ला अली खामनेई को मार दिए जाने की कड़ी निंदा करें। ईरानी दूतावास ने कहा था कि भारत स्थित इस्लामिक गणराज्य, ईरान का दूतावास दुनिया भर की आजाद और स्वतंत्रता की पक्षधर सरकारों से इस खतरनाक और कड़ी निंदा करने तथा अराजकता पैदा कर आक्रामकता के सामने खामोश नहीं बचने का आह्वान करता है। इसके बावजूद केंद्र सरकार की तरफ से निंदा का कोई बयान नहीं आया।

प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत की निंदा करने के बजाए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा था कि ऐसे विचारों का समाधान बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। उन्होंने दोहराया कि भारत की नीति हमेशा शांतिपूर्ण समाधान की रही है। सरकार का कहना है कि किसी भी संघर्ष की स्थिति में बातचीत का रास्ता अपनाना जरूरी है। मोदी की तरफ से अपेक्षित बयान नहीं आने विपक्षी दल मड़क गए। कांग्रेस संसदीय दल की अहं याद सौम्या गांधी ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की लुप्त होना पर मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर कहा कि उनका यह खतरा भारत की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर संदेश पैदा करता है।

आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने याद दिलाया कि कैसे पीएम मोदी ने भारत के राष्ट्रपति डीप्रसिंह रंझी की मौत के बाद एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था, जो मई 2024



में अजरबैजान में एक हेलीकोप्टर क्रैश में सतल लोगों के साथ मरने की खबरें मिलीं। संजय सिंह ने कहा मोदी जी, आज क्या हुआ? आपने ईरान के प्रेसिडेंट की मौत पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। आप ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत पर एक भी शोक दृष्टिकरण की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है।

भारत का किसी एक देश के लिए यह दृष्टिकरण कोई अपवाद नहीं है, बल्कि भारत की पारंपरिक विदेश नीति के सिद्धांतों के अनुरूप है। जिनमें भारत के अनुरूप है। ईरान के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा था कि ऐसे विचारों का समाधान बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। उन्होंने दोहराया कि भारत की नीति हमेशा शांतिपूर्ण समाधान की रही है। सरकार का कहना है कि किसी भी संघर्ष की स्थिति में बातचीत का रास्ता अपनाना जरूरी है। मोदी की तरफ से अपेक्षित बयान नहीं आने विपक्षी दल मड़क गए। कांग्रेस संसदीय दल की अहं याद सौम्या गांधी ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की लुप्त होना पर मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर कहा कि उनका यह खतरा भारत की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर संदेश पैदा करता है।

भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर समय और संवाद की अपेक्षा की। साथ ही ईरान द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के सहयोगियों

## देश में उच्च शिक्षा की तस्वीर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता

—डा. वीरेन्द्र भाटिया—



देश के अनेक राज्यों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) के ज्ञान और इस्तेमाल को उच्च शिक्षा के छात्रों के सिलेसब में शामिल किया जा रहा है, यह एक अच्छी पहल है। आज उच्च शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक आकर्षक बहलवा ली रही है, जो शिक्षण, सीखने और प्रशासनिक कार्यों को अधिक स्मार्ट और स्वस्थ बना रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को बदलने का एक सहायक औजार बन गई है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता छात्र की सीखने की गति और शैली को समझकर पाठ्यक्रम को अनुकूलित कर सकती है। यह पिछड़े छात्रों को सहायता देने के बजाय संतुलित पेशवा करने और उनके लिए विशेष ट्यूटोरियल प्रदान करने में मदद करती है। चोटबॉट और वीड्युअल कंटेंट छात्रों को 24-7 सहायता के प्रदान करते हैं, जिससे उनके सवालों के तुरंत जवाब मिल जाते हैं और वे अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। परीक्षा, और अन्य प्रशासनिक कार्यों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग समय और संसाधनों की बचत करता है, जिससे शिक्षक अपना ध्यान पढ़ाने और शोध पर लगा पाते हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े दूर दूरी का विश्लेषण करने, जटिल पैटर्न का विश्लेषण करना, जटिल पैटर्न का विश्लेषण करने और शोध प्रयोग के सारांश तैयार करने में शोधकर्ताओं की मदद करते हैं। जो आकाशिक अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। एआई-आधारित ट्यूटर्स (जैसे टैकस्ट-टू-टेक्स्ट और रीप्लै-टाइम अनुवाद) दिव्यांग छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री को सुचारु बनाकर समायोजी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से उन छात्रों को पहचाने जा सकते हैं जो छात्र हैं या जिन्होंने पिछड़े छात्रों को पहचानने में मदद की है। नैतियाद से बाधितों में प्रदान की गई है। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जा रहा है।

पीछे एक रणनीति थीक्यूबजुवन समाज पार्टी के डेटा को विश्लेषित करना। कई छोटे दलों और बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों को मैदान में उतारना या ताकि बहुजन वोट कई हिस्सों में बंट जाए और काशीराम की जीत मुश्किल हो सके। लेकिन काशीराम ने इस चुनौती को बेहद शांत और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार किया। उनका चुनाव प्रचार पारंपरिक नेताओं से बिल्कुल अलग था। वे गांव-गांव जाकर चौपालों में लोगों से संवाद करते थे और कहते थे कि यह चुनाव केवल एक सीट जीतने का चुनाव नहीं है, बल्कि बहुजन समाज को सत्ता में भागीदारी दिलाने का लड़ाई है। उनका सीधा और स्पष्ट संदेश लोगों को प्रभावित करता था।

इसी चुनाव में एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू थाक्यूबजुवन और उस समय के मुख्य चुनाव आयोग टी.एन. शेषन को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने इटावा लोकसभा सीट का चुनाव निरस्त कर दिया। यह घटना उस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई और चुनाव आयोग की सख्ती की मिसाल के रूप में देखी गई।

जब दोबारा चुनाव की घोषणा हुई तो इटावा का राजनीतिक मैदान और भी रोशनी का दौर था। इस बार कुल 48 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर आए। इसी बड़ी संख्या में प्रत्याशियों का मैदान में उतरना उनके लिए एक नई दिशा थी और सामाजिक न्याय का सवाल पूरे देश में प्रमुख राजनीतिक युवा बन चुका था। इसी दौर में काशीराम ने इटावा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। इटावा उस समय समाजवादी राजनीति का मजबूत शिवनाम था। यहां यादव, शाय, कुर्मी और अन्य पिछड़े वर्गों के साथ-साथ दलित समाज की भी बड़ी आबादी थी। यह क्षेत्र लंबे समय से समाजवादी विचारधारा से प्रभावित रहा था और स्थानीय राजनीति के पिछड़े वर्गों की भूमिका मजबूत थी। लेकिन उनका बल ही औपचारिक बहुजन संघर्षों में उभारने का प्रतीक बन गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उस समय के मुख्य चुनाव आयोग टी.एन. शेषन को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने इटावा लोकसभा सीट का चुनाव निरस्त कर दिया। यह घटना उस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई और चुनाव आयोग की सख्ती की मिसाल के रूप में देखी गई।

जब दोबारा चुनाव की घोषणा हुई तो इटावा का राजनीतिक मैदान और भी रोशनी का दौर था। इस बार कुल 48 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर आए। इसी बड़ी संख्या में प्रत्याशियों का मैदान में उतरना उनके लिए एक नई दिशा थी और सामाजिक न्याय का सवाल पूरे देश

काशीराम ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को लगभग बाइस हजार वोटों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस चुनाव में अकिशान उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। इस तरह काशीराम ने 47 प्रत्याशियों को हराकर पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया। यह जीत बहुजन समाज के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। संसद में पहुंचने के बाद काशीराम ने दलित-पिछड़े समाज के सवालों को राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से उठाया और सामाजिक न्याय की राजनीति को नई दिशा दी। इसी दौर में काशीराम और मुलायम सिंह यादव के बीच राजनीतिक समझ और मजबूत हुई। दोनों नेताओं ने महसूस किया कि अगर दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीति एक साथ आगे उठे उत्तर प्रदेश की सत्ता का संरक्षण बंद कर सकता है। यही सोच आम चलकर 1993 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के ऐतिहासिक गठबंधन में दिखाई दी। उस समय बना नाच-मिले मुलायम-काशीराम, हवा में उड़ गए जिस शौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े समय तक गुंजाता रहा और सामाजिक न्याय की राजनीति के नए अध्याय का प्रतीक बन गया।

आज भी काशीराम की राजनीतिक विरासत भारतीय राजनीति में स्पष्ट दिखाई देती है। बहुजन प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी का जो विमर्श उन्होंने शुरू किया था, वह आज भी कई राजनीतिक दलों की रणनीति और विचारधारा में दिखाई देता है। समाजवादी परंपरा को अगर बढ़ते हुए अखिलेश यादव ने जब वह घोषणा किया कि काशीराम जी की 92वीं वंशियों को बहुजन समाज दिसर (पीडीबी) संस्था के रूप में मनना जगता है, कि घोषणा इस बात का संकेत है कि काशीराम और मुलायम सिंह यादव द्वारा स्थापित सामाजिक न्याय की राजनीति आज भी प्रासंगिक और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।

## उच्च शिक्षा में शिक्षकों और छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (ए.आई.) महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी तकनीकों का उपयोग छात्रों के लिए निष्ठा सिद्ध करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।



उच्च शिक्षा में शिक्षकों और छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (ए.आई.) महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी तकनीकों का उपयोग छात्रों के लिए निष्ठा सिद्ध करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। आज उच्च शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक आकर्षक बहलवा ली रही है, जो शिक्षण, सीखने और प्रशासनिक कार्यों को अधिक स्मार्ट और स्वस्थ बना रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को बदलने का एक सहायक औजार बन गई है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता छात्र की सीखने की गति और शैली को समझकर पाठ्यक्रम को अनुकूलित कर सकती है। यह पिछड़े छात्रों को सहायता देने के बजाय संतुलित पेशवा करने और उनके लिए विशेष ट्यूटोरियल प्रदान करने में मदद करती है। चोटबॉट और वीड्युअल कंटेंट छात्रों को 24-7 सहायता के प्रदान करते हैं, जिससे उनके सवालों के तुरंत जवाब मिल जाते हैं और वे अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। परीक्षा, और अन्य प्रशासनिक कार्यों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग समय और संसाधनों की बचत करता है, जिससे शिक्षक अपना ध्यान पढ़ाने और शोध पर लगा पाते हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े दूर दूरी का विश्लेषण करने, जटिल पैटर्न का विश्लेषण करना, जटिल पैटर्न का विश्लेषण करने और शोध प्रयोग के सारांश तैयार करने में शोधकर्ताओं की मदद करते हैं। जो आकाशिक अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। एआई-आधारित ट्यूटर्स (जैसे टैकस्ट-टू-टेक्स्ट और रीप्लै-टाइम अनुवाद) दिव्यांग छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री को सुचारु बनाकर समायोजी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से उन छात्रों को पहचाने जा सकते हैं जो छात्र हैं या जिन्होंने पिछड़े छात्रों को पहचानने में मदद की है। नैतियाद से बाधितों में प्रदान की गई है। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जा रहा है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े दूर दूरी का विश्लेषण करने, जटिल पैटर्न का विश्लेषण करना, जटिल पैटर्न का विश्लेषण करने और शोध प्रयोग के सारांश तैयार करने में शोधकर्ताओं की मदद करते हैं। जो आकाशिक अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। एआई-आधारित ट्यूटर्स (जैसे टैकस्ट-टू-टेक्स्ट और रीप्लै-टाइम अनुवाद) दिव्यांग छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री को सुचारु बनाकर समायोजी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से उन छात्रों को पहचाने जा सकते हैं जो छात्र हैं या जिन्होंने पिछड़े छात्रों को पहचानने में मदद की है। नैतियाद से बाधितों में प्रदान की गई है। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जा रहा है।

## देश में उच्च शिक्षा की तस्वीर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता



देश के अनेक राज्यों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) के ज्ञान और इस्तेमाल को उच्च शिक्षा के छात्रों के सिलेसब में शामिल किया जा रहा है, यह एक अच्छी पहल है। आज उच्च शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक आकर्षक बहलवा ली रही है, जो शिक्षण, सीखने और प्रशासनिक कार्यों को अधिक स्मार्ट और स्वस्थ बना रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को बदलने का एक सहायक औजार बन गई है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता छात्र की सीखने की गति और शैली को समझकर पाठ्यक्रम को अनुकूलित कर सकती है। यह पिछड़े छात्रों को सहायता देने के बजाय संतुलित पेशवा करने और उनके लिए विशेष ट्यूटोरियल प्रदान करने में मदद करती है। चोटबॉट और वीड्युअल कंटेंट छात्रों को 24-7 सहायता के प्रदान करते हैं, जिससे उनके सवालों के तुरंत जवाब मिल जाते हैं और वे अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। परीक्षा, और अन्य प्रशासनिक कार्यों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग समय और संसाधनों की बचत करता है, जिससे शिक्षक अपना ध्यान पढ़ाने और शोध पर लगा पाते हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े दूर दूरी का विश्लेषण करने, जटिल पैटर्न का विश्लेषण करना, जटिल पैटर्न का विश्लेषण करने और शोध प्रयोग के सारांश तैयार करने में शोधकर्ताओं की मदद करते हैं। जो आकाशिक अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। एआई-आधारित ट्यूटर्स (जैसे टैकस्ट-टू-टेक्स्ट और रीप्लै-टाइम अनुवाद) दिव्यांग छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री को सुचारु बनाकर समायोजी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से उन छात्रों को पहचाने जा सकते हैं जो छात्र हैं या जिन्होंने पिछड़े छात्रों को पहचानने में मदद की है। नैतियाद से बाधितों में प्रदान की गई है। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जा रहा है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े दूर दूरी का विश्लेषण करने, जटिल पैटर्न का विश्लेषण करना, जटिल पैटर्न का विश्लेषण करने और शोध प्रयोग के सारांश तैयार करने में शोधकर्ताओं की मदद करते हैं। जो आकाशिक अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। एआई-आधारित ट्यूटर्स (जैसे टैकस्ट-टू-टेक्स्ट और रीप्लै-टाइम अनुवाद) दिव्यांग छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री को सुचारु बनाकर समायोजी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से उन छात्रों को पहचाने जा सकते हैं जो छात्र हैं या जिन्होंने पिछड़े छात्रों को पहचानने में मदद की है। नैतियाद से बाधितों में प्रदान की गई है। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जा रहा है।



